राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 11719/2023

1. सुरेंद्र एस. चौहान पुत्र हनुमंत सिंह चौहान, आयु लगभग 41 वर्ष, चौहानो की हवेली, गाँव बोहेड़ा, तहसील बड़ी सादडी, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

2. डॉ. कुलदीप सिंह झाला पुत्र लाल सिंह झाला, आयु लगभग 39 वर्ष, घर संख्या 70, गणपति विहार, चिराग कॉम्प्लेक्स, पनेरियो की मादरी, हिरण मागरी सेक्टर-4, उदयपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान अपने कुलसचिव के माध्यम से।

2. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान।

3. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय खेल बोर्ड, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान।

----उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता (गण) के लिए : डॉ. निखिल डुंगावत।

उत्तरदाता(गण) के लिए : श्री हेमंत बलानी।

माननीय श्री न्यायाधीश अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>03/01/2024</u>

यहाँ निम्नलिखित प्रार्थना खंड के साथ याचिका दायर की गई हैः-

"क) एक उचित आदेश या निर्देश द्वारा, आक्षेपित आदेश/पत्राचार दिनांक 27.05.2023 (अनुलग्नक 23) को कृपया रद्द किया जाए और अलग रखा जाए और,

ख) एक उचित आदेश या निर्देश द्वारा, प्रतिवादी को याचिकाकर्ताओं को सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) के पद पर बने रहने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाए।

ग) कोई अन्य उचित आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायाधिकरण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित समझे, कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जाए।"

2. याचिकाकर्ता, पूर्व अतिथि संकाय सदस्य होने के नाते, इस न्यायालय के समक्ष सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बाद असफल रहे हैं, जिसका विज्ञापन दिनांक 1.8.2017 (अनुलग्नक 25) के विज्ञापन द्वारा किया गया था।

3. स्पष्ट रूप से यहाँ विवाद को एक बहुत ही संकीर्ण दिशा में रखा गया है अर्थात क्या एक अतिथि संकाय सदस्य को केवल इसलिए पद पर बने रहने का अधिकार है क्योंकि वह पद, जिस पर वह पहले काम कर रहा था, अभी भी खाली है, इसके बावजूद कि विश्वविद्यालय को आगे की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है?

4. पहले संक्षिप्त तथ्य, जैसा कि कहा गया है। याचिकाकर्ता 2009 से सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) के पदों पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहे थे। वे 1999 से खाली पड़े स्वीकृत पद पर काम कर रहे थे। चार स्वीकृत पद हैं/थे जिन पर दो नियमित नियुक्तियां की गई हैं और दो अभी भी खाली हैं। हालांकि, प्रतिवादी ने जल्दबाजी में 27.05.2023 पर उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने 30.05.2023 पर एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन विश्वविद्यालय ने उस पर विचार नहीं किया, जिससे उन्हें वर्तमान याचिका दायर करनी पड़ी।

5. जाहिर है, विज्ञापन (उपरोक्त) से पहले याचिकाकर्ता अतिथि संकाय के सदस्यों के रूप में सेवा करने के लिए काफी लंबे समय तक बने रहे क्योंकि नियमित रूप से नियुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे। विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद, याचिकाकर्ताओं ने भी चयन प्रक्रिया में भाग लिया, लेकिन वे पर्याप्त रूप

से उपयुक्त नहीं पाए गए और इस प्रकार नियमित पदों पर नियुक्त होने में असफल रहे।

6. दो नियमित नियुक्तियों के बाद, यह स्पष्ट होता है कि चार नियमित पदों में से दो पद अभी भी खाली हैं और इसी वजह से याचिकाकर्ताओं ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है ताकि यह मांग की जा सके कि उक्त दो पदों को भरने की अनुमति दी जाए और उन्हें अतिथि संकाय में बने रहने की अनुमति दी जाए। वास्तव में, इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं का यह दूसरा प्रयास है जिसमें इस तरह के परमादेश की मांग की गई है क्योंकि उन्होंने पहले एस. बी. सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 8637/2016 वाली एक और रिट याचिका दायर की थी, जिसका निपटारा मेरे विद्वान भाई जे. दिनेश मेहता की अध्यक्षता वाली एक समन्वय पीठ ने दिनांक 08.05.2023 (अनुलग्नक 21) के आदेश के माध्यम से किया था।

7. आदेश दिनांकित 08.05.2023 (अनुलग्नक 21) की प्रासंगिकता, विपरीत होने के कारण, नीचे यहाँ पुनः प्रस्तुत की गई हैः-

> "6. इस न्यायालय का विचार है कि यह प्रतिवादी-विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार है कि वह दो पदों या चार पदों पर नियुक्ति के लिए जाए और यह न्यायालय विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को जारी रखने के लिए परमादेश जारी नहीं कर सकता है, जब नियमित रूप से चयनित उम्मीदवार शामिल हुए हों।
>
> 7. जो भी हो सकता है।
>
> 8. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विश्वविद्यालय ने दिनांक 12.09.2022 के पत्र के माध्यम से सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) के दो और पदों को भरने की अनुमति मांगी है, ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय को सहायक निदेशक के पद की आवश्यकता है, जिस पर याचिकाकर्ता अतिथि संकाय के रूप में बने हुए हैं।
>
> 9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का निपटारा याचिकाकर्ताओं को अपनी नियुक्ति जारी रखने के लिए प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दायर करने के निर्देश के साथ किया जाता है।

10. यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसा कोई अभ्यावेदन पसंद किया जाता है, तो प्रतिवादी-विश्वविद्यालय कानून के अनुसार इस पर विचार करेगा, विशेष रूप से राज्य सरकार को उसके द्वारा भेजे गए 12.09.2022 दिनांकित पत्र के आलोक में, जो यह स्थापित करता है कि विश्वविद्यालय को चार सहायक निदेशकों की आवश्यकता है।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए उपरोक्त निर्देश केवल याचिकाकर्ताओं की शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इसे एक विशेष तरीके से प्रतिनिधित्व तय करने का आदेश नहीं माना जा सकता है।"

8. याचिकाकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया, जिसे दिनांक 27.5.2023 (अनुलग्नक 23) के आक्षेपित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

9. तत्काल रिट याचिका विचाराधीन रहने के दौरान, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आगे का मामला बंद कर दिया, एक बार फिर, दिनांक 01.11.2023 के आदेश के माध्यम से विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व पर विचार करने और नए आदेश पारित करने का निर्देश दिया, यदि वास्तव में दो खाली पदों पर सेवाओं की आवश्यकता थी ताकि याचिकाकर्ताओं को पहले की तरह अतिथि संकाय में समायोजित किया जा सके।

10. हालाँकि, प्रतिद्वंद्वियों की दलीलों को सुनने के बाद, यह स्पष्ट होता है कि दो नियमित नियुक्तियों के बाद, चार स्वीकृत पदों में से, विश्वविद्यालय ने काम को इस तरह से विभाजित किया है कि अन्य दो रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता नहीं है।

11. केवल इसलिए कि स्वीकृत पद खाली पड़े हैं, किसी व्यक्ति को उसी पर नियुक्ति के लिए अपना दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, यदि नियोक्ता को स्वीकृत पदों पर सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, आक्षेपित आदेश यह स्पष्ट करता है कि, न केवल इस स्तर पर, नियमित नियुक्तियों द्वारा भरे गए दो पदों पर ही सेवाओं की आवश्यकता होती है, बल्कि भविष्य में जब भी दो रिक्त पदों पर आगे की सेवाओं की आवश्यकता होगी, याचिकाकर्ताओं को अतिथि संकाय सदस्यों के रूप में नियुक्त करने के लिए पहली पसंद दी जाएगी। बशर्ते कि विश्वविद्यालय इस तरह की व्यवस्था करना चाहता है, इसके

बजाय नियमित नियुक्तियों का चयन करना चाहता है, जैसा कि पहले किया गया था। इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनाया गया है।

12. अंत में, मैं यह कह सकता हूं कि मनीष गुप्ता और अन्य आदि बनाम अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति और अन्य आदि एआईआर ऑनलाइन (2022) एससी 576 मामले में दिए गए शीर्ष न्यायालय के फैसले पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की निर्भरता गलत है। उसी की प्रासंगिकता नीचे दी गई हैः

> "12. गवर्नमेंट कमला राजा गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट ऑटोनॉमस कॉलेज, ग्वालियर के प्राचार्य द्वारा 24 जून, 2016 को जारी विज्ञापन, जो अपील पेपर बुक के संलग्नक पी-2 में है और प्रिंसिपल, एस. एम. एस. गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज, ग्वालियर, एम. पी. द्वारा 2 जुलाई, 2016 को जारी विज्ञापन, जो अपील पेपर बुक के संलग्नक पी-3 में है, से पता चलता है कि नियुक्तियां उम्मीदवारों को उचित चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद की जानी थीं। यद्यपि श्री नटराज, विद्वान ए. एस. जी. ने पुरजोर आग्रह किया है कि अपीलार्थियों की नियुक्तियां विज्ञापनों की प्रकृति से, अतिथि व्याख्याताओं के रूप में थीं न कि तदर्थ कर्मचारियों के रूप में, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अपीलार्थियों की नियुक्ति तदर्थ आधार पर की गई थी। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक तदर्थ कर्मचारी को किसी अन्य तदर्थ कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है और उसे केवल एक अन्य उम्मीदवार द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसे नियमित प्रक्रिया का पालन करके नियुक्त किया जाता है। इस संबंध में रतन लाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर और हरगुरप्रताप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय के आदेश पर भरोसा किया जा सकता है।
>
> 13. मामले के उस दृष्टिकोण में, हम यह नहीं पाते हैं कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिकाकर्ताओं को नियमित चयन होने तक अपने 1 (1985) 4 एस. सी. सी. 43 2 (2007) 13 एस. सी. सी. 292 संबंधित पदों पर काम करना जारी रखने का निर्देश देकर कोई त्रुटि की गई थी। हालाँकि, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किया गया निर्देश कि रिट याचिकाकर्ता यू. जी. सी. परिपत्र के अनुसार वेतन प्राप्त करने के हकदार होंगे, टिकाऊ नहीं

है। विज्ञापनों में स्वयं स्पष्ट रूप से कहा गया था कि चयनित उम्मीदवारों को उक्त समिति द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मानदेय का भुगतान किया जाएगा।"

13. उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वास्तव में परिस्थितियाँ विपरीत हो चुकी हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात किसी भी तरह से याचिकाकर्ताओं की मदद नहीं करता है, इसके विपरीत यह याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क के खिलाफ जाता है।

14. एक परिणाम के रूप में, याचिकाकर्ता का यह दावा कि एक विश्वविद्यालय को उन्हें अतिथि संकाय के रूप में नियुक्त करने के लिए अनिवार्य रूप से मजबूर किया जाना चाहिए, केवल इसलिए कि दो स्वीकृत पद अभी भी खाली हैं, अस्तित्व में नहीं रहता है क्योंकि इस स्तर पर उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी।

15. तदनुसार याचिका खारिज की जाती है।

16. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।